

प्रेषक,

डी० सैथिल पाण्डेयन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक)

देहरादून: दिनांक: ०७ जुलाई, 2015

विषय: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष कम अवमुक्त अवशेष राज्यांश (Short Fall) की धनराशि रू० 468.35 लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-रा०प०का०/172/लेखा-2/केन्द्रांश-राज्यांश/2015-16 दिनांक 22 अप्रैल, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश रू० 468.35 लाख कम अवमुक्त होने के कारण किये गये अनुरोध के दृष्टिगत अनुदान संख्या-30 (एस०एसी०पी०) के अन्तर्गत रू० 468.35 लाख (रुपये चार करोड अड़सठ लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01-04-2015 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु पूँजीगत पक्ष के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपभोग करने से पूर्व नियमानुसार आगणन की स्वीकृति सहित वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सक्ष स्तर से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- (3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
- (4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

- (5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- (6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायें।
- (7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
- (8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-30 के अधीन लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 800-अन्य व्यय, 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना, 0101 सर्व शिक्षा अभियान, 20-सहायक/अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

03— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं०-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01-04-2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में प्रशासकीय विभाग के स्तर से ही जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डी० सेंथिल पाण्डियन)

सचिव

सं०— /XXIV(1)/2015-11/2014 टी०सी० तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया भविष्य में प्रस्ताव निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से ही शासन को प्रस्तुत किया जाय।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

21.15

(नन्दन सिंह विष्ट)

अनु सचिव।